

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2019—फाल्गुन 24, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अजय सिंह, (भा.प्र.से.-1983), अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करता है.

2. श्री अमिताभ जैन, (भा.प्र.से.-1989), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

3. श्री देवी दयाल सिंह, (भा.प्र.से.-2000), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है।
4. श्री रीना बाबा साहेब कंगाले, (भा.प्र.से.-2003), सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है।
5. श्रीमती संगीता पी. (भा.प्र.से.-2004), विशेष सचिव, (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं विशेष सचिव, (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, (स्वतंत्र प्रभार), आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।
6. श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, भा.व.से., संचालक, उद्यानिकी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को वापस सौंपता है।
7. प्रो. (डॉ.) प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फल विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आदेश पर्यन्त संचालक, उद्यानिकी एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्रमांक 1356/169/21-ब/छ.ग./19.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री सतीश चन्द्र वर्मा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	श्री शैलेन्द्र दुबे	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3.	श्री आलोक बक्शी	अतिरिक्त महाधिवक्ता
4.	श्रीमती फौजिया मिर्जा	अतिरिक्त महाधिवक्ता
5.	श्री सलीम काजी	उप महाधिवक्ता
6.	श्री जितेन्द्र पाली	उप महाधिवक्ता
7.	श्री अमरेन्द्र नाथ भक्ता	उप महाधिवक्ता
8.	श्री हरप्रीत सिंह अहलुवालिया	उप महाधिवक्ता
9.	श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव	उप महाधिवक्ता
10.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	उप महाधिवक्ता
11.	श्री रजनीश सिंह बघेल	उप महाधिवक्ता
12.	श्री आलोक निगम	शासकीय अधिवक्ता
13.	श्री संजय अग्रवाल	शासकीय अधिवक्ता
14.	श्री अरूण शुक्ला	शासकीय अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)
15.	श्रीमती सुनीता जैन	शासकीय अधिवक्ता
16.	संगीता मिश्रा	शासकीय अधिवक्ता
17.	श्री राहुल झा	शासकीय अधिवक्ता
18.	श्री विमलेश बाजपेयी	शासकीय अधिवक्ता
19.	श्री राघवेन्द्र वर्मा	शासकीय अधिवक्ता
20.	श्री रवीश वर्मा	शासकीय अधिवक्ता
21.	श्री के. के. सिंह	शासकीय अधिवक्ता
22.	श्री घनश्याम पटेल	शासकीय अधिवक्ता
23.	श्री विक्रम दीक्षित	शासकीय अधिवक्ता
24.	श्री राहुल मिश्रा	उप शासकीय अधिवक्ता
25.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	उप शासकीय अधिवक्ता
26.	श्री राजेश सिंह	उप शासकीय अधिवक्ता
27.	श्री आनंद वर्मा	उप शासकीय अधिवक्ता
28.	श्री सुभाष यादव	उप शासकीय अधिवक्ता
29.	श्री सुदीप वर्मा	उप शासकीय अधिवक्ता
30.	श्री रवि भगत	उप शासकीय अधिवक्ता
31.	आई. लकड़ा	उप शासकीय अधिवक्ता

No. F 1356/169/21-B/C.G./2019.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint the following Law Officers in the Advocate General Office, Bilaspur specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutors for the High Court of Chhattisgarh :—

S. No. (1)	Name of the Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Satish Chandra Verma	Additional Advocate General
2.	Shri Shailendra Dubey	Additional Advocate General
3.	Shri Alok Bakshi	Additional Advocate General
4.	Smt. Fouzia Mirza	Additional Advocate General
5.	Shri Salim Qazi	Deputy Advocate General
6.	Shri Jitendra Pali	Deputy Advocate General
7.	Shri Amrendra Nath Bhakta	Deputy Advocate General
8.	Shri Harpreet Singh Ahluwalia	Deputy Advocate General
9.	Shri Chandresh Shrivastava	Deputy Advocate General
10.	Shri Devendra Pratap Singh	Deputy Advocate General
11.	Shri Rajneesh Singh Baghel	Deputy Advocate General
12.	Shri Aalok Nigam	Government Advocate
13.	Shri Sanjay Agrawal	Government Advocate
14.	Shri Arun Shukla	Government Advocate
15.	Smt. Sunita Jain	Government Advocate
16.	Sangeeta Mishra	Government Advocate
17.	Shri Rahul Jha	Government Advocate
18.	Shri Vimlesh Bajpai	Government Advocate
19.	Shri Raghvendra Verma	Government Advocate
20.	Shri Raveesh Verma	Government Advocate
21.	Shri K. K. Singh	Government Advocate
22.	Shri Ghanshyam Patel	Government Advocate
23.	Shri Vikram Dixit	Government Advocate
24.	Shri Rahul Mishra	Dy. Government Advocate
25.	Shri Krishna Kumar Dewangan	Dy. Government Advocate

(1)	(2)	(3)
26.	Shri Rajesh Singh	Dy. Government Advocate
27.	Shri Anand Verma	Dy. Government Advocate
28.	Shri Subhash Yadav	Dy. Government Advocate
29.	Shri Sudeep Verma	Dy. Government Advocate
30.	Shri Ravi Bhagat	Dy. Government Advocate
31.	I. Lakda	Dy. Government Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्रमांक 638/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	कापूबहरा प.ह.नं. 35	2.598	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2019

क्रमांक 641/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	घुंछापुर प.ह.नं. 37	3.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	रायपुर जलाशय योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	104	0.04
	119	0.12
	99	0.06
	120	0.06
	121	0.10
	101	0.01
	98	0.04
	81	0.14
	92	0.05
	93	0.10
	88	0.06
	87	0.12
	86/1	0.16
	89	0.01
	83	0.14
	45	0.08
	76	0.02
	80	0.10
	44	0.18
	41	0.40

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-भरतपुर

(ग) नगर/ग्राम-चुटकी, प.ह.नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 हेक्टेयर

(1)	(2)	(1)	(2)
49	0.16	3	0.10
52	0.16		
46	0.16	योग	3.85
58	0.12		
214	0.16	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-डौकीझिरिया व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.	
61	0.44		
63	0.10	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
225	0.12		
13	0.20		
30	0.04	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
8	0.10	नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर, दिनांक 5 फरवरी 2019

शुद्धि पत्र

क्रमांक/948/न.ग्रा.नि./2017.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है, कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1052, बिलासपुर दिनांक 25-02-2017 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के तहत जारी सूचना जो कि छत्तीसगढ़ राजपत्र में भाग-1 में दिनांक 16-06-2017 को मुद्रित हुई है, में भैरमगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं के स्थान पर तखतपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं पढ़ा जावे.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 01/L.G./2019/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 07 days from 11-12-2018 to 17-12-2018 along with permission to leave headquarters from 11-12-2018 to 18-12-2018 & earned leave for 05 days from 14-01-2019 to 18-01-2019 along with permission to leave headquarters from 12-01-2019 to 21-01-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 256 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 02/L.G./2019/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge Family Court, Manendragrah, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-12-2018 to 14-12-2018 along with permission to leave headquarters from 09-12-2018 to 16-12-2018, earned leave for 06 days from 30-12-2018 to 04-01-2019 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters after working hours of 24-12-2018 till 04-01-2019 & earned leave for 03 days from 31-01-2019 to 02-02-2019 along with permission to leave headquarters from 31-01-2019 to 03-02-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+05 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 03/L.G./2019/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 27-12-2018 to 29-12-2018 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters from the morning of 23-12-2018 till the evening of 30-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 04/L.G./2019/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 09 days from 24-12-2018 to 01-01-2019 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 05/L.G./2019/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 03 days from 10-12-2018 to 12-12-2018 along with permission to leave headquarters after the National Lok Adalat on 08-12-2018 till before the Court hours of 13-12-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sawant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)
